भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.5051
मंगलवार, 1 अप्रैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (शक)को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के पंजीयकों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

5051. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीयकों (आरसीएस) के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ऐसे कितने आरसीएस के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों सहित राजस्थान में कितनी सहकारी समितियों और एआरडीबी के अभिलेखों को पहले ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ, मान्यवर । मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की है और यह कार्यान्वयनाधीन है ।

(ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की यह परियोजना मंत्रालय की 'आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण की अम्ब्रेला परियोजना का एक हिस्सा है । परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय को बढ़ाना और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों (RCS) के साथ सहकारी समितियों के पारदर्शी और कागज-रहित लेनदेन हेतु एक डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । इस परियोजना के अधीन विकसित सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी अधिनियमों के अनुरूप होगा ।

अब तक छत्तीसगढ़ सहित 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (केरल को छोड़कर) ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है और मंत्रालय द्वारा 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं । आईटी हार्डवेयर के प्रापण और सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अब तक 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 18.55 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जारी की गई है । 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपना आईटी हार्डवेयर का प्रापण कर लिया है ।

(ग) और (घ) दीर्घ-कालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैली 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की है । नाबार्ड परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक, 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा, दिनांक 26.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, हार्डवेयर का प्रापण, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य सहित 11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की 7.17 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है । आज की तारीख तक राजस्थान राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत हार्डवेयर की खरीद अभी शुरू की जानी है ।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य के लिए पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु केंद्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन कुल 6,781 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4,937 पैक्स पहले ही ERP पर ऑनबोर्ड (कंप्यूटरीकृत) किए जा चुके हैं ।

उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में ERP पर ऑनबोर्ड किए गए (कंप्यूटरीकृत) सहकारी समितियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत	ERP पर ऑनबोर्ड किए गए
1	उदयपुर	210	182
2	भीलवाड़ा	359	221

दिनांक 25 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में पैक्स कंप्यूटरीकरण का डेटा

क्रम सं.	जिला	संस्वीकृत पैक्स	कंप्यूटरीकरण पैक्स
1	अजमेर	208	182
2	अलवर	248	168
3	बांसवाड़ा	226	108
4	बरन	123	66

5	बाड़मेर	398	240
6	भरतपुर	282	85
7	भीलवाड़ा	359	220
8	बीकानेर	234	221
9	बूंदी	158	143
10	चित्तौड़गढ़	320	283
11	चुरू	192	119
12	दौसा	176	133
13	डूंगरपुर	134	71
14	गंगानगर	334	231
15	हनुमानगढ़	238	164
16	जयपुर	377	318
17	जैसलमेर	58	10
18	जालोर	187	129
19	झालावाड़	212	184
20	झुंझुनू	268	216
21	जोधपुर	298	187
22	कोटा	161	149
23	नागौर	324	141
24	पाली	154	118
25	सवाई माधोपुर	221	175
26	सीकर	262	242
27	सिरोही	81	64
28	टोंक	209	176
29	उदयपुर	339	308
	कुल	**6,781**	**4,851**